

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)**पीठासीन अधिकारी - प्रभा गौतम (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 012/2020 (नि.पं.) (GCMS 2020/00029)	दायर दिनांक 29.07.2020	निर्णय दिनांक 15.01.2026
---	---------------------------	-----------------------------

अनवान

1. उदयसिंह पिता किशनसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी मौखमपुरा जागीर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
2. नारायणसिंह पिता किशनसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी मौखमपुरा जागीर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

निगराकारान**बनाम**

1. राजकीय प्राथमिक विद्यालय मौखमपुरा जागीर जरिये प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय मौखमपुरा जागीर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
2. ग्राम पंचायत नपानिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नपानिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

गैर-निगराकारान

उपस्थिति :- सीएम जणवा
अनुपस्थित
एक तरफा

निगराकारान
गैर-निगराकार संख्या 1
गैर-निगराकार संख्या 2

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994**-:: निर्णय ::-**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगराकारान ने एक निगरानी प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरुद्ध गैर निगराकारान के विरुद्ध अधीनस्थ ग्राम पंचायत नपानिया पंचायत समिति भदेसर द्वारा जारी पट्टा संख्या 011 दिनांक 21.01.2013 जो कि गैर-निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया है के संबंध में प्रस्तुत की गई है।

इस पर निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारान को जरिये नोटिस के तलब किया गया एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत नपानिया से मूल अभिलेख तलब किया गया। दिनांक 24.03.2021 को गैर निगराकार संख्या 01 स्वयं हाजिर आये। दिनांक 27.05.2022 को गैर-निगराकार संख्या 01 अनुपस्थित रहे। दिनांक 24.05.2024 को गैर-निगराकार संख्या 02 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से गैर-निगराकार संख्या 02 के विरुद्ध



कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। प्रकरण में विकास अधिकारी भदेसर के पत्रांक/पसभ/संस्थापन/2024-25 दिनांक /05/2024 से अधीनस्थ ग्राम पंचायत नपानिया का मूल अभिलेख प्राप्त हुआ है जो कि पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में बहस पत्रावली को सुना गया।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस पत्रावली में निगरानी मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि निगराधीन पट्टा पंचायती राज अधिनियम की धारा 158 के अंतर्गत जारी किया गया है जो कि उक्त धारा के प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि उक्त धारा में वर्णित शर्तानुसार ऐसे आवंटियों को निःशुल्क पट्टा आवंटित किया जा सकता है जो अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ा वर्ग के कारीगर, मजदूरी करने वाले श्रमिक एवं भूमिहीन व्यक्ति या विकलांग एवं खानाबदोश गाड़ी लौहार आदि को निश्चित सीमा अर्थात् 150 वर्गगज तक दिया जा सकता है फिर भी अधीनस्थ ग्राम पंचायत विपक्षी संख्या 02 द्वारा विपक्षी संख्या 01 को अपने क्षेत्राधिकार से परे जाते हुए 4500 वर्गफीट का निःशुल्क पट्टा जारी कर दिया गया जो वैधानिक दृष्टि से भी त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

विपक्षी संख्या 01 को जिस स्थान का पट्टा जारी किया गया उसके संबंध में वर्ष 2002 में प्रार्थीगण/निगराकार संख्या 01 व 02 को पृथक-पृथक पट्टे कीमतन जारी किये जाकर मौके पर भौतिक रूप से कब्जा सिपुर्द किया गया तथी से निगराकार अपने-अपने भूखण्ड पर शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन उन्ही भूखण्डों को संयोजित करते हुए गैर-निगराकार संख्या 01 को जो पट्टा संख्या 11 वर्ष 2013 में जारी किये गया वह पूर्णतया गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर-निगराकार संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायत अधिनियम की धारा 145 से 152 में वर्णित प्रावधानों की किसी प्रकार से कोई पालना नहीं गई, क्योंकि यदि किसी प्रकार से कोई सूचना पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा जारी की जाती है तो निगराकार अधीनस्थ ग्राम पंचायत के समक्ष ही अपने आक्षेप प्रस्तुत कर देते जिससे कार्यवाही नहीं जा सकती।

अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 11 जो जारी किया गया जिसका माप पूर्व से पश्चिम 90 फीट तथा उत्तर से दक्षिण 50 फीट कुलिया 4500 वर्गफीट का जारी किया गया जिसके संबंध में पंचायत अधिनियम में स्पष्ट प्रावधाना है कि आबादी के अनुसार भूखण्ड की दर वर्णित करते हुए अलग-अलग आबादी अनुसार दरों का निर्धारण किया गया है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्देशों की कोई पालना नहीं करते हुए गैर-निगराकार संख्या 01 को जो पट्टा जारी किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

निगराकारान वर्ष 2002 से तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टा संख्या 47 एवं 29 की पालना में मौके पर सिपुर्द किये गये कब्जे अनुसार काबिज होकर उपयोग



उपभोग करते चले आ रहे थे लेकिन अभी हाल ही में गैर-निगरकारान द्वारा हमारे पट्टेशुदा भूखण्ड से कब्जा हटाने हेतु मौके पर आये तथा नवीन पट्टा गैर-निगरकार संख्या 01 के पक्ष में होना बताने पर जानकारी हुई।

गैर-निगरकार संख्या 02 ने नियमों एवं मौके की स्थिति को नहीं देख कर मात्र ग्राम पंचायत कार्यालय में बैठे-बैठे ही पूरी कार्यवाही कर मात्र निगरकार को परेशान करने की नियत से नियमों के विपरित पट्टे जारी किये जो निरस्त योग्य है। अंत में प्रार्थना की गई कि निगरकारान की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर गैर-निगरकार संख्या 01 को जारी पट्टा दिनांक निरस्त फरमाया जावे। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता निगरकार ने अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का परिशीलन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। प्रकरण में तथ्यों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया :-

97. Power of revision and review by Government.- (1) The State Government may, either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing Committee or Sub-Committee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any party unless such party has a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The State Government may stay the execution of any such decision or order prejudicial to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.

(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any person interested, at any time within ninety days of the passing of an order under Subsec.

(1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to Sub-sec. (1) and in Sec. (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्हीं भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती है। राज्य सरकार



की अधिसूचना क्रमांक एफ4(10)परावि/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुर्नस्थापित कर दिया गया है। निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी में विवादित पट्टे के संबंध में उसकी विधिकता/औचित्य के संबंध में प्रश्न उठाया गया है, ऐसी स्थिति में हस्तगत निगरानी इस न्यायालय में पोषणीय पाया जाता है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख की अवलोकन/परिशीलन किया। पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में प्रक्रियात्मक प्रावधान के प्रावधान किये गये है। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 140 से 168 तक में प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये है।

158. **Allotment of lands to weaker sections.-**

(1) The Panchayat may allot Abadi land up to [300 sq. yards] in village Abadis at concessional rate to members of Scheduled Caste, scavengers, Scheduled Tribes, Backward Classes, village artisans, landless persons dependent on wage labour, IRDP selected families, Handicapped, Nomatic Tribes, Gadia Lohar who do not own house sites/house and also to flood victims whose house have been washed away or the house sites have been rendered unfit for future habitation due to floods [and patta of such land may be issued in Form XXIII-C]

[IA. the Panchayat may allot abadi land upto [300 Sq. Yards] in village Abadi at concessional rate to ex-service men in bordering Panchayat Samiti areas.]

(1)	Rates to be charged from such allottees will be as under :	
(a)	In villages having population less than 1000 (1991 census).	Rs. 2/- per sqr. mtr.
(b)	In villages having population from 1001 to 2000 (1991 census).	Rs. 5/- per sqr. mtr.
(c)	In villages having population more than 2000 (1991 census).	Rs. 10/- per sqr. mtr.

Provided that the State Government may allot such lands free of charges to any such category of persons.

[Provided further that in case of allotment of abadi land to the families of below poverty line, the Panchayat may allot the land free of charge.]

[(2-A) The Panchayat may allot Abadi land upto 300 Sq. Yards free of charge to nomadic sheep reares.]

[(2-B) The State Government may allot Abadi land to oustees of irrigation project, equal to the house sites or house owned by them subject to maximum of 300sq. yards free of charge.]

(2) Abadi land allotted free of charge shall be non-transferable. A seal in block letters "NOT FOR SALE" shall be affixed on the face of all such Pattas. In case any allottee transfers or sells such house site/house to any other persons, allotment shall automatically stand cancellation, ownership shall vest in the Panchayat along with construction or material lying thereon and transferee will be ejected to trespasser on such Abadi Land.



- [(3A) Thirty percent of Land allotted under this rule shall be allotted to widows and divorce women.]
- (4) Panchayat may however by a resolution in the meeting, decide to allot such land by negotiation to such trespasser on market price on compassionate grounds.
- (5) The allottee shall be debarred form any subsequent allotment in future
- (6) Provisions contained in Sub-rules (3), (4) and (5) shall also be applicable for shop sites allotted to Scheduled Caste and Scheduled Tribes etc., in Panchayat areas.
- (7) For allotment of houses sites to flood victims at another place/places, the Panchayat concerned shall invite applications from such persons along with an undertaking that in case of allotment of house sites at another place/places, the house sites washed away in flood aiong with material shall vest in the Panchayat concerned free from all encumbrances.
159. **Allotment of lands on concessional price.-**
- (1) The Panchayat may allot plots up to 500 sq. yards from Abadi land available with to Ex-Service Military Personnel (Non-commissioned ranks) who do not own any Abadi land on priority basis, at 50% of the market price as mentioned in Sub-rule (5) of Rule 152.
- [(2) The Panchayat may also allot plots upto 1500 sq. yards in abadi area, on priority basis, for construction of godowns/ offices to-
- (i) Primary Agricultural Cooperative Society/Large Sized Multipurpose Marketing Society, at 50% of the Market price as mentioned in sub-rule (5) of Rule 152;
- (ii) Gram Sewa Sahakari Samiti or Kray Vikary Sahakari Samiti, free of charge subject to confirmation by the State Government.]

हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत नपानिया से प्राप्त अभिलेख का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में नियम 140 से नियम 159 तक में भूखण्डों के प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये है, जो कि बाध्यकारी है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 नियम 158 में भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये है। पंचायत गांव आबादियों में 150 वर्ग गज की की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडा वर्गों के सदस्यों को, गांव कारगारों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं हैं और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनमें गृह-स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी। उप-नियम 2 में वसूली योग्य दरे प्रावधित की गई है। इसके साथ ही कुछ व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों के लिए निःशुल्क आवंटित कर सकेगी। उप-नियम 3 के तहत इस प्रकार आवंटित की गई आबादी भूमि अन्तरणीय होगी। ऐसे सभी पट्टों पर बडे अक्षरों में “विक्रय के लिए



नहीं” की मुहर लगाई जायेगी। नियम 159 में भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन के प्रावधान प्रावधित किये गये हैं। पंचायत उसमें उपलब्ध आबादी भूमि में से 500 वर्ग गज तक के भूखण्ड पूर्विकता के आधार पर भूतपूर्व सेना के ऐसे कर्मियों को (जो कमीशंड रैंकों के नहीं हैं) जिनके पास किसी भी आबादी भूमि में स्वयं का मकान नहीं है, नियम 152 के उप-नियम (5) में उल्लिखित बाजार कीमत की 50 प्रतिशत पर आवंटित कर सकेगी।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। प्रार्थी/निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी में मुख्य रूप से न्यायालय के विचारणार्थ विवादित भूखण्ड का कब्जे में होने एवं निगराधीन पट्टे की प्रक्रियात्मक त्रुटि के बिन्दु उठाये गये हैं। जहां तक विवादित भूखण्ड का कब्जे में होने का प्रश्न है इस संबंध में प्रार्थी/निगराकार द्वारा न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार से विवादित भूखण्ड पर काबिज होने के संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया एवं यह तथ्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य का मोहताज है। प्रकरण में प्रार्थीगण/निगराकारान द्वारा अपने नाम पर पूर्व में पट्टा जारी किये जाने का तथ्य उठाया गया है, किन्तु निगराकारान द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रार्थीगण/निगराकारान का कब्जा हो। केवल मात्र अभिवचनों से इस तथ्य को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। हस्तगत निगराधीन पट्टा राजकीय प्राथमिक विद्यालय मौखमपुरा जागीर को निःशुल्क आवंटित किया गया है, जहाँ तक विद्यालय को निःशुल्क आवंटन का प्रश्न है इस संबंध में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 नियम 162 के तहत ग्राम पंचायत को विद्यालय को निःशुल्क आवंटन किये जाने के प्रावधान प्रावधित है, ऐसी स्थिति में निगराकार कोई ठोस आधार पत्रावली पर प्रस्तुत करने में पूर्णतया असफल रहे हैं।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा निगरानी के माध्यम से ग्राम पंचायत नपानिया पंचायत समिति भदेसर द्वारा जारी पट्टा संख्या 011 बुक संख्या 187 दिनांक 21.01.2023 के संबंध में निगराकार अपनी निगरानी न्यायालय के समक्ष प्रमाणित कराये जाने में पूर्णतया असफल रहे हैं, जिससे निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होकर एवं सारहीन एवं बलहीन होने से खारीज की जाती है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत नपानिया का अभिलेख मय निर्णय की प्रमाणित प्रति के मार्फत विकास अधिकारी भदेसर के भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 15.01.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रभा गौतम)

अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

